मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

 **राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 8**

22.11.2011 को उत्तर के लिए

**''मध्य प्रदेश में नदियों और झीलों का संरक्षण और जीर्णोद्धार''**

**8. श्रीमती माया सिंह :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नदियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में नदियों और झीलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उन नदियों और झीलों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को इन कार्यों के लिए कितनी निधि आवंटित की गयी है; और

(ग) जीर्णोद्धार कार्य के अंतर्गत उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदूषण मुक्त बनाई गई नदियों और झीलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में खान, क्षिप्रा, चम्बल, नर्मदा, टोन्स, कालीसोट, बेटवा और मन्दाकिनी नदियों के नौ प्रदूषित नदी भागों को अभिज्ञात किया है और इसमें अशोधित सीवेज को निस्तारित करने वाले 14 शहरों को भी अभिज्ञात किया है । नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत तैयार स्कीमों को 11 शहरों में कार्यान्वित किया गया है जिनमें सीवर लाइनों का बिछाना, सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण, अल्प लागत शौचालय, शवदाहगृह और नदी तटाग्र विकास आदि शामिल हैं । इस समय नदियों के प्रदूषण उपशमन की स्कीमें, होशंगाबाद, रेवा और चित्रकूट शहरों में कार्यान्वित की जा रही हैं । देश के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) भी कार्यान्वित कर रहा है । मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में रानी तालाब, रेवा, सागर झील, सागर और शिवपुरी झील, शिवपुरी के संरक्षण हेतु स्कीमों को स्वीकृत किया है ।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 425 लाख रू0 और मध्य प्रदेश में एनएलसीपी के अंतर्गत झील संरक्षण के लिए 60 लाख रू0 जारी किए हैं ।

(ग) 11 शहरों में नदी प्रदूषण उपशमन के लिए स्वीकृत स्कीमों को पूरा कर लिया गया है । रेवा में रानी तालाब के संरक्षण के लिए स्वीकृत स्कीमों के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*